

श्री. विष्णु शर्मा

प्रेषक,

श्री बाबू राम,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आपुक्त सर्व सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
अनुभाग-2, लखनऊ ।

राजेश्वर कुमार तिवारी

मुख्य सचिव,
लखनऊ

राजस्व अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 1996

विषय:- वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् उरामें हस्तक्षेप न किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-4723/1-7-91-404/91, दिनांक-16-9-91 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद सम्बन्धित निगम/संस्था/विभाग द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं है तथा प्रत्येक निगम/संस्था/विभाग से वसूली व्यय समान रूप से लिया जाय तथा इसकी छूट का कोई प्राविधान या अपवाद न किया जाय । संग्रह व्यय वसूली प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण धनराशि पर ही प्रत्येक दशा में देय होगा ।

CRA

10/6/96
Rajiv Rana

2- समय-समय पर कायालय महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा लेखा परीक्षा आडिट हेतु भेजे गये लेखा परीक्षा दल द्वारा किये गये निरीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा संस्था/निगम/विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने के कारण वसूली प्रमाण-पत्र वापस लौटा दिये गये किन्तु उन वसूली प्रमाण-पत्रों पर देय संग्रह धनराशि को वसूली नहीं की गई जिससे राजस्व क्षति हुई। यह स्थिति आपत्तिजनक है।

अतः अनुरोध है कि एक बार किसी संस्था/निगम/विभाग से वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद यदि उक्त संस्था/निगम/विभाग द्वारा देय धनराशि

.....2.....

7/6/96

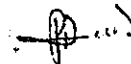
生

4488

:- 2 :-

सीधे प्राप्त कर वसूली प्रमाण-पत्र वापस मांगा जाता है तब भी संग्रह व्यय देय होगा जिसकी प्राप्ति के बाद वसूली प्रमाण-पत्र वापस किया जाय। कृपया इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि शासन को होने वाली राजस्व क्षति से बचा जा सके तथा इस मामले में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का आडिट पुस्तक न बने।

भवदीय,

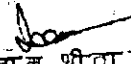

बाबू राम
प्रमुख सचिव।

संख्या - 128611/1-7-96-404/91-रा0-7 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आक्षेपक जा र्षवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपने अधीनस्थ संस्था/निगम/विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत होने के पश्चात् वे वसूली की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें। यदि उनके द्वारा हस्तक्षेप करके आंशिक वसूली कर ली जाती है अथवा वसूली प्रमाण-पत्र वापस मांगा जाता है तो भी वसूली प्रमाण-पत्र की सम्पूर्ण धनराशि पर दिए संग्रह व्यय राजस्व विभाग को देय होगा जिसके अनुसार संग्रह व्यय की वसूली भी सुनिश्चित करते हुए इसे राजस्व विभाग को उपलब्ध करा फेंगे अन्यथा वसूली प्रमाण-पत्र वापस मांगे जाने पर राजस्व विभाग द्वारा वापस करना सम्भव नहीं होगा।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त सहाय सचिव, उ०प्र०।
- 4- कार्यालय महालेखाकार, आडिट-2, उ०प्र०, इलाहाबाद।

आज्ञा से,


रामसाहाय लाल श्रीवास्तव
विशेष सचिव।